17.20 hrs.

*ISSUE OF TICKETS BY AIR INDIA WITHOUT 'P' FORMS

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति, महोदय, कुछ अर्से से सदन के सामने यह मामला है। मुझे बातें तो बहुत करनी हैं लेकिन मैं केवल चार मुद्दों पर बोलने वाला हूं। सब से पहला मामला पी फार्म के बारे में है जिस के बारे में इसी सत्र में सवाल पूछा गया था। मेरा और श्री दाजी का सवाल था। दाजी साहब सदन में नहीं थे तब मंत्री जी ने जो जवाब दिया था उस में और जो मेरी जानकारी है उस में काफी अन्तर है। समय बचाने के लिये मैं ने स्पीकर साहब को जो चिट्ठी लिखी है उस में से ही एक अनुच्छेद पढ़ना चाहता हूं

"When the Minister was persistently asked about the break-up of the 317 cases which have been reported, the Minister gave the following figures:—

90 are exempted categories; 45 had regular 'P' form clearances; 55 have been found not to have regular 'P' form clearances; the remaining 130 cases are being investigated by the Enforcement Directorate."

May I point out that the Secretary of the Civil Aviation Ministry, in his reply dated the 9th June, 1966, to my letter has informed me as under?

"As far as 'P' form cases are concerned out of the 305 cases mentioned, more than one-third have been found to be covered actually by 'P' forms or were in respect of travel which did not require the issue of 'P' forms. In almost similar number of cases, onquiries have shown certain elements of doubts or difficulties in establishing the charge. It is likely that in about 40 to 50 cases, further investigations will show the existence of a *prima facie* case and steps are being taken to pursue them from this point of view and to take appropriate action."

अब दोनों में फर्क यह आ गया है कि यह कह रहे थे कि जांच हो रही है और सिविल एविएशन के सचिव कहते हैं कि जांच होने के बाद कुछ शक और कुछ दिक्कत पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की सफाई करें कि यह दिक्कत और अड़चन क्या है? क्या यह बात सही नहीं है कि इस से सम्बन्धित जितने कागजात हैं उन को खत्म किया गया है जानबूझ कर और इसलिए सरकार का जो जांच विभाग है उन को जांच करने में तकलीफ हो रही है? उसी तरह जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उस के अधिकार बहुत सीमित हैं। एक तो जितने रुपये में पैसे दिये गये हैं उन मामलों में वह कुछ नहीं कर सकता है और जहां विदेशी मुद्रा का सवाल आता है उस में वह कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह सी० बी० आई० के हाथ में मामला क्यों नहीं दिया ताकि जो दस्तावेज हैं उन को वह कब्जे में ले सकता और जो रुपये के मामले हैं उन के बारे में भी वह तहकीकात कर सकता? मैं चाहता हूं कि इसकी वह जरा सफाई करें और इस को सदन को बतायें। वह इस को छिपायें नहीं कि असली बात क्या है? दस्तावेजों को जानबूझ कर नष्ट किया गया है या नहीं?

अब मैं दूसरे मामले पर आता हूं और वह उप्पल साहब का मामला है जिस के बारे में फोटो स्टेट मैं ने सदन के सामने रखा था और मैं ने यह इल्जाम लगाया था कि उप्पल साहब को आप के एयर इंडिया के बड़े अधिकारियों ने कहा कि आप साहब फंस रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिये और किसी निजी

*Half-an-Hour Discussion.

[श्री मधु लिमये]

कम्पनी में नौकरी कीजिये ताकि जो अनुशासन की कार्रवाही है वह आप के खिलाफ न करनी पड़े। श्री संजीव रेड्डी साहब के लिए मैं यह अंग्रेजी में कह देना चाहता हूं कि कारपोरेशन की जो "डिसिप्लिनरी जुरिसडिकशन" है उस से भागने के लिए क्या उस को कहा गया कि इस्तीफा दे दो? क्या एक निजी कम्पनी में उन को नौकरी दिलवाई गई है? पी० ए० सी० की पचासवीं रिपोर्ट के पृष्ठ 105 की ओर मैं आप का ध्यान खींचूंगा। इस के पहले एक बात हमें याद रखनी है कि इस में एक पत्र है फ्राम युवर्स सिन्सिअरली एस० भूतलिंगम, आई० सी० एस० टू माई डीयर बाम, आई० सी० एस०। एक ही इस का वाक्य मैं पढ़ता हूं।

"I think you could also indicate to a few select firms the procedure outlined above."

इस का क्या नतीजा होता है? एक नतीजा यह होता है कि आयात और निर्यात सम्बन्धी ये जो जितने परवाने हैं, परमिट हैं, लाइसेंस हैं, कुछ घूसखोरी से और कुछ बेईमानी कर के पा लिये जायें तो उस में कोई एंटरप्राइज की, उद्योगशीलता की, एंटरप्रेन्योरिशिप की बात नहीं होती है। क्या नतीजा होता है। एक ही वाक्य आप देख लें। यह पृष्ठ 55 पर है:

"Asked whether the biggest transactions were entered into with Messrs Amin Chand Pyarelal group of firms, he replied in the affiramative and stated that their share, which was 9% in imports and 12% in exports of steel in 1959 increased to 59% and 60% respectivly, in 1960."

वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इस वक्त हमारी अर्थ व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र है, समाजवाद और पूंजीवाद है उनका जो झगड़ा है उसको आप एक मिनट के लिए छोड़ दें। अगर स्पर्धा के ऊपर आधारित जो पूंजीवाद है उसी को आप चलायें—फीयर्सली कम्पीटीटिव इकोनोमी—तो उस में जो उद्योगशीलता है, पैदावार बढ़ाने की तबीयत है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या यह पूंजीवाद है या समाजवाद है कि आप चार सौ बीसी करके परमिट और लाइसेंस ले लेते हैं और एक साल में जिन का नौ प्रतिशत आयात में और बारह फी सदी निर्यात में हिस्सा है वह 59 परसेंट और 60 परसेन्ट हो जाता है। यह लोगों को आप इंसेंटिव दे रहे हैं? इसको क्या आप उद्योगशीलता कहते हैं:

Mr. Chairman: The hon. Member will address me and not "Aap".

श्री मधु लिमये: आपका मतलब आप से ही होता है।

उप्पल साहब सरकारी क्षेत्र से हट कर निजी कम्पनी में नौकर हो गए। पी० ए० सी० ने यह जो बेईमानी बिजनेस या डिसआनेस्ट बिजनेस और भ्रष्ट सरकार या नौकरशाही दोनों का जो गठबन्धन है उसके नतीजों की ओर ध्यान दिलाया है 105 पृष्ठ पर एक ही वाक्य मैं पढ़ता हूं:

"Further many officers of the controller's office have after retirement, retrenchment, resignation, or dismissal found employment in one or other private firms including those in this group......"

—that is, the Aminchand Pyarelal Group—

"...... dealing with import-export of steel."

मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। सरकारी नौकरी में बेईमानी करने वाले जो लोग निकाले जाते हैं या जो खुद निकल जाते हैं उनको निजी क्षेत्र स्वागतम् कहने के लिये तैयार बैठा रहता है। यह एक बुनियादी

मामला है । मैं चाहता हूं कि इसको श्री रेड्डी साहब ठीक तरह से देख लें ।

अब यह भूतपूर्व जनरल मैनेजर का मामला उठा था । तारीख मुझे ठीक ठीक याद नहीं है लेकिन मैंने खुद इसको शायद 18 मार्च को उठाया था । यह बख्शी के लड़के का मामला नहीं था । मुझे खुशी है अगर सचमुच आपने बी० आर० पटेल साहब को सज़ा देने के लिए वहां से निकाल दिया है और इसके लिये मैं आपको बधाई भी देता हूं । लेकिन अगर उनको बचाने के लिए आपने ऐसा किया है तो मैं अपनी बधाई वापिस लेता हूं क्योंकि उनके खिलाफ और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये । वह बहुत रो रहे हैं यह मैंने सुना है । इसलिये कि उनको एयर इंडिया इंटरनैशनल से हटा दिया गया है । एक सवाल जब मैंने पूछा था तब दो कालम छपा था टाइम्ज आफ इंडिया में लेकिन अब की बार जब मैंने सवाल पूछा तो बिलकुल नहीं छपा । इसका कारण यह है कि एयर इंडिया के उसको इश्तहार मिलते हैं । मैं पत्रकारों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं । सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है यह मैं बता रहा हूं । उनको बड़े बड़े इश्तहार मिलते हैं । आखिरकार अखबार वाले भी क्या करें । उनको जिन्दा तो रहना होता है । लेकिन आप इस बात का खयाल करें और आज की जो बहस है उस में हमारी बात भी और आपकी बात भी आनी चाहिये । पी० आई० बी० जो रहता है उसको दोनों की बात लाने की कोशिश करनी चाहिये । मैं यह नहीं कहता हूं कि आपकी बात न छपे । आपकी भी छपे और हमारी भी । दोनों की छपनी चाहिये । अखबार वालों को आप विज्ञापन देते हैं । इसलिए ऐसा न हो कि हमारी बात न छपे और आपकी छप जाये । कम से कम इसके बारे में आप ज़रा कोशिश करें ।

बी० आर० पटेल साहब का मामला बहुत पुराना है । 22 फरवरी को यह उठा था । मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री यहां बैठे हुए हैं । मैं ऐसे ही किसी मामले को यहां नहीं उठाता हूं । बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद ही उठाता हूं । मामला जब पक जाता है और कोई नतीजा नहीं निकलता है तब मैं उस मामले को सदन में उठाता हूं । बिना नोटिस के भी नहीं उठाता हूं ।

मैं इस पत्र से एक अनुच्छेद ही पढता हूं ।

"it is necessary that some special Central Government agency is entrusted with the task of probing the travels of Air India International General Managers' non-dependent relatives....

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : किस का पत्र है ?

श्री मधु लिमये : यह वित्तमंत्री साहब को मैंने लिखा है । इस में नान डिपेंडेंट रेलेटिव्स का जिक्र है । मतलब मेरा लड़के से है मैंने ज़रा ठीक भाषा में लिखा है कि वह जांच करे । लेकिन वह इसको कर नहीं रहे हैं । इसलिए मुझे यहां कहना पड़ रहा है ।

"One of these relatves happens to be a senior executive of the Indian Oil Corporation and had gone abroad posing as an invitee of a pharmaceutical firm. This gentleman never had in the past any connection with the pharmaceutical industry. How is it then that the Reserve Bank approved his journey on such a mission? I suspect that this was done because the person happened to be a relative of the Air India International boss."

इस में इन लोगों कि बहुत सी गंदी बाते भी हैं । मैं उनको यहां नहीं कहूंगा । अगर आप सी० बी० आई० से जांच करवायेंगे तो मुझ से जरूर इत्तिला ले लें ।

एक और मामला विदेशी मुद्रा का इससे सम्बन्धित है यह असैनिक उड्डयन

[श्री मधु लिमये]

सेवाओं के सैक्रेटरी को लिखा हुआ पत्र है, इस सफे का जिस की चर्चा यहां पर हुई थी। 29 मार्च का यह खत है। इसका छठवां हिस्सा फिनलांटिक चार्टर नाम की एक अमरीकी कम्पनी के हवाई जहाज के बारे में है। वह हवाई जहाज मद्रास में आया था और विदेशी मुद्रा में पैसा दिया गया।

इस मामले को भी मैं पढ़ता हूं :

"This matter refers to handling of Messrs. Finlantic Charter. A sum of Rs. 900 (In U.S. dollars 189) was collected for this charter flight from a foreign operator by the airport manager of the A.I.I. at Madras, Mr. Sheorey three or four years ago. The amount was handed over to the exchange by this gentleman all right. But, however, when Major Srinivasan, manager, Madras, saw these dollar bills on the cashier's table, he greedily took them away and paid this amount in Indian currency by way of a cheque or in cash. Since the original receipt mentioned payment in dollars made by the American Captain Engelbercht the manager asked the staff to make out a duplicate receipt in rupees. This is a fact which can be easily checked by any investigating agency or an inquiry committee empowered to do so."

"Now, I ask, whether there is a rule to the effect that payment cannot be accepted in Indian currency from foreign operators, whether under the exchange laws and regulations in force in India, no foreigner can bring in Indian rupees, and whether he must make payment in foreign currency only. I understand that the dollar bills illegally collected by this Major were later on smuggled to New York".

दूसरी बातें जो इन के दूसरे गन्दे काम हैं, मैं इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता हूं।

मैंने जो सीधी सी बात पूछी थी कि जो डालर बिल्ज़ आए थे, क्या उन को जेब में डाला गया था या नहीं उस का जवाब ही नहीं दिया गया है। कहा गया है कि उस वक्त कानून यानी भुगतान में लूपहोल था, और रुपी में पेमेंट किया जा सकता था। मान लीजिए कि वह लूपहोल था, लेकिन मेरा सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह बात ठीक है या नहीं कि डालर्ज़ में पेमैंट किया गया और जब मेजर श्री निवासन ने कैशियर के टेबल पर उन डालर्ज को देखा, तो उन की आंखें ललचाईं और उन्होंने उन को जेब में डाल लिया और स्टाफ को रूपीज़ में एक डुप्लिकेट रिसीट बनाने के लिए कहा। पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं। वह हमारी तरफ भी कुछ इनायत की नजर रखें और कभी कभी हमें बुला लिया करें। हम सब बातें उन के सामने रखेंगे।

शंकर साहब का यह जवाब आया है :

"Regarding Finlantic charter, the handling charges for the charters were received by the Madras Air India representative in December, 1962. This was in accord with the practice that was prevalent at the time in cases of exchange charter operator. Corrective action has since been taken and handling charges are being recovered only in foreign currency".

इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त कानून में कोई खामी थी जिस की बदौलत विदेशी मुद्रा में देना जरूरी नहीं था, रूपी में भी दिया जा सकता था। लेकिन मेरा वह सवाल नहीं है। उस खामी को दूर करने के बारे में जो आश्वासन दिया गया है, अगर वह सही है तो मैं उस का स्वागत करता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या यह सही नहीं है कि चूंकि उस वक्त कानून में खामी थी, इस लिए उस का इस्तेमाल कर के अमरीकी साहब ने जो डालर्ज़ दिये थे

उनका मगर श्रीनिवासन ने जेब में डाल लिया। जहां तक कानून की खामी का सम्बन्ध है, उस को अगर ये बड़े बड़े लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उस का इस्तेमाल कर के रूपीज़ में डुप्लिकेट रिमिट दे दी गई। वित्त मंत्री इस बात की सफ़ाई करें कि एन्फोर्समेंट और सी० बी० आई० के अधिकार क्या हैं। क्या वे मुकदमा भी चला सकते हैं या जिस को आरबिट्रेशन कहते हैं वही कर सकते हैं।

चूंकि मेरी बात का साफ जवाब शंकर साहब ने नहीं दिया है, इसलिए मैं मंत्री साहब से सीधा जवाब चाहता हूं। अपने पत्र के अनुच्छेद 6 में मैंने जो कुछ कहा है मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं इस तरह की टाल-मटोल वाली नीति पसन्द नहीं करता हूं। मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि अगर वह आज उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो वह बाद में इसका उत्तर दे दें। मुझे कोई जल्दी नहीं है मेरी इच्छा केवल यह है कि सत्य बाहर आए।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Air India is in international competition and has always enjoyed a very enviable reputation. As a matter of fact, it is not individuals with whom we are concerned; we are very much concerned about the reputation of Air India which is in international competition.

There is a considerable amount of scandal which hangs about the "P" forms. Why it is that the Air India International comes into the play, I do not understand. If there are any loopholes, may I know whether Air India has taken any interest to see that those loopholes are plugged, and whether your Ministry has looked into this matter? Your Enforcement Branch may be blamed, anybody may be blamed, but can you take any steps to see that Air India which is in international competition is not brought into these dirty deals, and if Air India has to do anything with these "P" forms, will you please let us know what steps you have taken to see that it does not get mixed up with these scandles?

Shri Daji (Indore): I will recall for the benefit of the House and the Minister that the Committee on Public Undertakings, about a year back, may be more than a year back, in its report itself had drawn the attention of the Government to the misuse by Air India of "P" forms. I would like to know whether the Government has enquired into the allegations and findings of the Committee, and if so, how is it that the Government has not yet sent a reply to the Committee or the House?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): You mean the Committee on Public Undertakings?

Shri Daji: We have made a report and we have found that these "P" forms are being misused. May I know if the Government has made an enquiry, and if so, what is the result of this enquiry?

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) क्या यह सही है कि बख्शी साहब के मामले में उप्पल साहब गवाही देने के लिए नहीं आए, उन को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही नहीं देना चाहता हूं मैं सामने नहीं जाना चाहता हूं; अगर हां तो क्या सरकार इस बारे में न्यायिक जांच करवायेगी?

जिन अफसरों पर कुछ आरोप थे, उस आरोपों को धोने के लिए उन को एयरइंडिया से हटा कर प्राइवेट सर्विस में लगा दिया गया। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि अगर किसी अफसर के खिलाफ कुछ आरोप हैं, तो जब तक उस का केस चलता है और पूरे तथ्य सामने नहीं आते हैं, तब तक उस को किसी अन्य जगह नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी?

Shri Sanjiva Reddy: I am glad this opportunity is given, and I must thank

[Shri Sanjiva Reddy]

Mr. Limaye for bringing this before the House, and through the House before the public.

There is nothing hush-hush in this business. As my hon. frined Mr. Mathur put it, we should all be careful to see that the reputation of Air India is not sullied. If there is a mistake, some irregularities committed by one or two officials, I am one with the leaders of the opposition that we should take note and see that they are punished. Nobody is anxious to save a person who is guilty, but before a man is found guilty, if we begin condemning him, it will be unfortunate.

I have got all the information at my disposal about Mr. B. R. Patel. Last time I thought the hon. Member, Mr. Limaye, was actually referring to Mr. Bakshi, but then I could catch later on that he was trying to get information about Mr. B. R. Patel. Even before that I had enquired into the case, and now I have full information before me. It was enquired into. Neither did he go without a "P" form, nor his sons. This is the information I have got again verified.

The position was this. He and his wife were allowed to travel and they had the "P" forms. But later on they decided that they could not go. "P" forms were secured in the name of his son and daughter-in-law; they travelled no doubt; and the other son travelled some time ago. All this happened years ago. He went at his own cost. One son and daughter-in -law went at the invitation of Lufthansa, and they had "P" forms in their own names; they did not borrow the "P" forms of their father and mother.

Shri Madhu Limaye: That was not my point.

Shri Sanjiva Reddy: What is your point? I would like to know.

श्री मधु लिमये : मैंने कहा था कि यह साहब फार्मास्युटिकल फर्म्ज की कांफरेंस में इन्वाइटी बन कर चले गए और इस के आधार पर रिजर्व बैंक से पी फार्म लिया।

He made a misrepresentation to the Reserve Bank. He had nothing to do with the pharmaceutical industry.

Shri Sanjiva Reddy: He did not go in the Air India plane at all. Once he went at his own cost, I do not know for what business, pharmaceutical conference or something. The second son and daughter-in-law went in Lufthansa; they had their own "P" forms. I am stating a fact; if the information I am giving is wrong, I am willing to be corrected. You should not throw mud against officers unless they are found guilty. Nobody is anxious to save them but at the same time we will have to protect them also.

Shri Daji: The question is missed. When did not belong to the line, why did the Reserve Bank of India allow him to have "P" form?...... (*Interruptions.*)

श्री मधु लिमये : वित्त मंत्री उस का जवाब दें।

Shri Sanjiva Reddy: I did not know about the conference and all that. I am particular only about this: the father, the General Manager was not directly responsible. Which conference he attended and so on is some other thing. The Enforcement Directorate has found that 55 people travelled without "P" forms. I agreed to place the list on the Table. Here is the list and if you permit me I will place it. [*Placed in Library, see* No. LT-6698/66]. If somebody commits a crime, why hide it?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): If you place the list on the Table, the address also should be given there.

Shri Sanjiva Reddy: I have absolutely no objection to place this list. If the Leaders of the opposition knows anything more, I shall get that information also. While answering the question, I had assured them that I will place on the Table of the House. Here is the list and I am placing it on the Table.

Mr. Chairman: All right; you may place it on the Table.

Shri Sanjiva Reddy: If they have any information, I would like to know and take further action. Uppal's case is there and some irregularities are being looked into; by the Enforcement Directorate. The Air India will naturally take action. He is still in service. My friend mentioned about two or three officers resigning and securing jobs in the private sector. The legal advice is there; the law department has examined this case. When they resign, there is no option for the corporation. There is a clause in the agreement that the corporation can send away an employee with one month's notice and the employee also can resign and walk out after a month's notice; it is reciprocal, both ways. When they resign, you cannot compel them. But if you find them guilty of certain criminal irregularities, you can certainly take action against them even if they had resigned and gone to private sector.

श्री मधु लिमये : फोटो स्टैट रखा गया है, उस पर एक्शन लीजिए आप।

Shri Sanjiva Reddy: That is what exactly I am saying. Nothing prevents the Enforcement Directorate from taking action. It is not that they are completely free. It is still under enquiry by the Directorate and I am sure some action will be taken.

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब तक निपटारा नहीं होता तब तक वह सर्विस नहीं कर सकते।

श्री संजीव रेड्डी : सर्विस में नहीं हों तो भी एन्क्वायरी कर सकते हैं।

There is absolutely no difficulty. Even if not in service, the enquiry will continue. I do not want to read the rule although I have it before me. They do not go scotfree the moment they resign.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा था कि वह त्याग पत्र देने के बाद में भी गैरसरकारी क्षेत्र में सर्विस नहीं कर सकते जब तक कि पूरा मामला निपट नहीं जाता है।

Mr. Chairman: There is no prohibition to that.

Shri Sanjiva Reddy: I am very glad the Committee on Public Undertakings had made some very good suggestions; we are looking into them. We have already taken action on some of them; we will take action on the others. It is our desire to improve the working of the Air India and IAC both. We are really thankful to the Committee for making very good suggestions.

It is true that some of the officers have not behaved properly and the Corporation's name is being brought into ridicule by them. But let us not forget the very good work it has done. It started only about nine years ago as a public sector concern. The growth of Air India since nationalisation has been phenomenal. The revenue has grown from 7 crores in 1954-55 to 30 crores in 1964-65, in nine years.

The total capital employed increased from Rs. 10 crores in 1954-55 to Rs. 35 crores at the end of 1964-65. Also, it has built up a very good reputation all over the world as a very well-managed institution.

Shri Hanumanthaiya (Bangalore City): Late-going.

Shri Sanjiva Reddy: Not Air India. My hon. friend is a little late here; therefore he did not follow what has been happening. Now, I have information about the good work done by Air India. Our public undertakings

[Shri Sanjiva Reddy]

are there, and some of them have been doing very well. Because of some unfortunate troubles let us not try to belittle the good work done by the public undertakings, and Air India is one of them. We must really congratulate the Chairman, the General Manager and all others who have been responsible in building up this good institution. Let me assure my hon. friend Shri Madhu Limaye that if he brings to my notice any irregularity, I shall discuss it with the Chairman and the Directors and try to see that it is corrected, or the people concerned are punished. But let us be careful about the reputation of Air India being kept in good condition.

Shri Harish Chandra Mathur: We have always supported Air India on the floor of this House for their excellent performance and we are quite aware of its enviable reputation. But my basic question was, why do they not take certain steps, or whether those steps have already been taken or not, at the suggestion of the Committee on Public Undertakings or by themselves or at your own initiative, so that such things do not at all occur and the Air India is not at all concerned with such things.

Shri Sanjiva Reddy: I am very glad that my hon. friend has brought this point. All these cases occurred before October, 1965: in 1962, 1963 and 1964 and 1965. All these are old cases. Corrective measures have been taken in the last six to nine months. I do not think such things are happening now. If anybody brings to my notice any such thing, even then we can correct it.

श्री मधु लिमये : मेजर श्रीनिवासन के केस के बारे में नहीं बताया ।

17.48 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 9, 1966/Sravana 18, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS—II—1193 (Ai) LS—18-10-66—970.